

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ज्वालियर

समक्ष - एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक ३५४-दो/२०१४ - विरुद्ध - आदेश
 दिनांक - १६-१-२०१४ - पारित व्याया - अनुविभागीय
 अधिकारी चंदेरी जिला अशोकनगर - प्रकरण क्रमांक
 २/२०१३७१४ अपील

श्रीमती भागवती वाई पत्नि महाराज सिंह
 ग्राम बड़ेरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर
 विरुद्ध

---आवेदक

१- गोपाल सिंह पुत्र सरदार सिंह लोधी
 ग्राम बड़ेरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर

२- चन्द्रपाल सिंह पुत्र जयराम सिंह लोधी
 ग्राम चक बड़ेरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर

---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
 (अनावेदकगण के अभिभाषक श्री पी०के०तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक ५ - ८ - २०१६ को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी जिला
 अशोकनगर व्याया प्रकरण क्रमांक २/२०१३७१४ अपील में पारित
 आदेश दिनांक १६-१-२०१४ के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व
 संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार
 चंदेरी के समक्ष म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा

(JN)

१०८

109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की ग्राम दिनोला स्थित भूमि सर्वे नंबर 216/1/6 राजस्व रिकार्ड में चतुर पुत्र शिवुआ के नाम अंकित है किन्तु चतुरा ने यह भूमि विक्रय कर लिखा पढ़ी कर दी है तथा पति के जमाने से उसके कब्जा चला आ रहा है। चतुरा द्वारा बसीयत भी उसके हित में की है इसलिये इस भूमि पर उसका नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार चंदेरी ने बसीयत को अधार पर मानकर प्रकरण क्रमांक 14 अ-6/12-13 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपर्यांत आदेश दिनांक 28-3-2013 पारित करके ग्राम दिनोला स्थित भूमि सर्वे नंबर 216/1/6 रकमा 1.000 हैक्टर पर आवेदक का नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के समक्ष अनावेदकगण ने दिनांक 11-10-13 को अपील क्रमांक 2/2013-14 प्रस्तुत की एवं अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी ने धारा-5 के आवेदन पर उभय पक्ष की सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिनांक 16-1-14 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के समक्ष तहसीलदार के आदेश

19

MM

दिनांक 28-3-13 के विलम्ब दि. 16-1-14 को प्रथम अपील प्रस्तुत हुई है अर्थात् अपील प्रस्तुत करने में 9 माह 17 दिवस के लगभग विलम्ब हुआ है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुये क्षमा किया है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र पृष्ठ क- 12 से 15 पर संलग्न है जिनके अवलोकन पर पाया गया कि धारा-5 के आवेदन में इस प्रकार का विवरण है:-

“ अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थीगण आवश्यक पक्षकार थे किन्तु पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थीगण परिवेदित हुये हैं तथा अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।”

जब अनावेदकगण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये गये हैं उन पर तहसील के आदेश सौख्यना नहीं है तब अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिये गये विवरण एंव पुष्टिकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है।

1. म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959 - धारा 47 सहपृष्ठि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा-5 - विलम्ब की माफी के लिये आवेदन फाइल - आवेदक को अपने विवाद मात्र से इस आधार पर बंचित नहीं किया जा सकता कि उसका आवेदन परिसीमा से बर्जित है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म०प्र०) - धारा 47 सहपृष्ठि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा-5 - विलम्ब की माफी - उदार रूख अपनाया जाना होगा, जब तक कि आवेदन घोर उपेक्षा से अथवा सदभावना के अभाव से ग्रसित न हो।

1/92

(M)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी चन्द्रेरी ने प्रकरण क्रमांक २/२०१३-१४ अप्रैल में पारित आदेश दिनांक १६.१.१४ से अपील प्रस्तुत करने में हुये लगभग ९ माह १७ दिवस के विलम्ब को क्षमा करने में किसी प्रकार की ऋटि नहीं की है।

५/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं अनुविभागीय अधिकारी चंद्रेरी जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक २/२०१३-१४ अप्रैल में पारित अंतरिम आदेश दिनांक १६-१-२०१४ उचित होने से यथावत् रखा जाता है।



(प्र०क० ३५४ सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर